ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-12* January- 2018
Innovation The Research Concept

भारत – पाकिस्तान संबंध : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

चॉदनी नायक
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर, म.प्र.

सारांश

भारत एवम् पाकिस्तान ऐसे दो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिनके बीच आजादी से लेकर अब तक आपसी संबंधी कभी–भी मधुर नहीं बन सके हैं इसका कारण यह है कि पाकिस्तान भारत को कभी–भी अपना मित्र नहीं मान पाया और शत्रुता का कोई–भी अवसर उसने कभी छोड़ा नहीं है। जबकि भारत की तरफ से हमेशा यह प्रयास किया गया कि वह पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करे। लेकिन एक ओर पाकिस्तान काश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास करता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वह अपनी सरजमीं पर आंतक का पालन–पोषण करके भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। और अब चीन की शह पाकर वह भारत को लगातार परमाणु युद्ध की धमकी भी दे रहा है। दरअसल दक्षिण एशिया में अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिये महाशक्तियों ने भी कभी भारत–पाकिस्तान संबंधों को मधुर नहीं होने दिया। ऐसी स्थिति में, भारत– पाकिस्तान संबंध किस दिशा में जायेंगे यह तो भविष्य ही तय करेगा।

मुख्य शब्द : भारत,पाकिस्तान, परमाणु युद्ध, महाशक्ति, मित्रता, मधुर संबंध।

प्रस्तावना

प्राचीन काल में भारत को 'सोने की चिड़ियाँ' कहा जाता था लेकिन जब भारत में ब्रिटिश शासकों ने प्रवेश किया तब उन्होंने 31 दिसम्बर,1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हुये व्यापार के माध्यम से समस्त भारतवासियों को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। ब्रिटिश शासकों ने लम्बे वर्षों तक न सिर्फ भारत के सिंहासन पर राज किया बल्कि देश में साम्प्रदायिकता का बीज भी बो डाला। जिसका परिणाम देश–विभाजन के रूप में सामने आया और आखिरकार 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान एवम् 15 अगस्त, 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पर्व मनाया। पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटिश शासन की ''फूट डालो और शासन करो'' की नीति का परिणाम है, लेकिन विभाजन के पश्चात् जब विश्व मानचित्र पर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत एवम् पाकिस्तान अस्तित्व में आये तब ऐसा प्रतीत हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों ही राष्ट्र एक–साथ मिलकर सहयोग, भाईचारे, घनिष्ठ मित्रता के साथ अपने संबंधों को मजबूत स्थापित करेंगे। लेकिन शरणार्थियों की समस्या विस्थापित सम्पत्ति देशी राज्यों की संवैधानिक स्थिति, नहरी पानी, सीमा–निर्धारण, वित्तीय और व्यापारिक समायोजन, जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर की संवैधानिक स्थिति तथा कच्छ पर पाकिस्तान के आक्रमण के प्रश्नों को लेकर दोनों देशों में गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। समय के साथ–साथ अन्य विवादों की तीव्रता कम हो गई परंतु काश्मीर विवाद आज–भी दोनों देशों के संबंधों में विष घोल रहा है। भारत–पाकिस्तान के बीच काश्मीर समस्या– ''एक ऐसे ज्वालामुखी के समान है, जो समय–समय पर लावा उगलता है।

काश्मीर के विलय के प्रश्न पर भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीष श्री गजेन्द्र गढ़कर ने जो विचार व्यक्त किये थे वे काश्मीर पर भारत की स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देते हैं, श्री गढ़कर के शब्दों में – ''समय पर काश्मीर सरकार एवम् भारत सरकार के बीच किये गये समझौतों एवम् दोनों राज्यों में विकसित संवैधानिक कानून के आधार पर आज स्थिति यह है, कि जम्मू–काश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है, जिसका भारतीय संघ से पृथ्थककरण जम्मू–काश्मीर तथा भारतीय संविधान में संशोधन बिना संभव नहीं है।''[1]

इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब–जब तनाव उत्पन्न हुआ है तब–तब रिश्तों को सुधारने की पहल हमेशा–ही भारत की ओर से की गई है लेकिर हर बार पाक का दो मुँहापन उभरकर हमारे सामने आया। सेना के हुक्मरानों और कट्टरपंथी संगठनों ने सभी कवायदों पर पानी फेर दिया

और इसके बदले में हमें आतंकी हमलों के रूप में संकेत दिये कि दोस्ती का सफर आगे न बढ़ाया जाये। वाजपेयी जी की दिल्ली लाहौर बस यात्रा के बदले संघर्ष, वाजपेयी–मुर्शरफ आगर शिखरवार्ता के बदले भारतीय संसद पर आतंकी हमला, भारत–पाकिस्तान युद्ध विराम समझौता के बदले मुंबई 26/11 आतंकी हमला, नरेन्द्र मोदी– नवाब शरीफ उफा वार्ता और मोदी जी की लाहौर यात्रा के बदले उरी, गुरूदासपुर, पठानकोट, पुंछ में आतंकी हमले ऐसे ही इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

2 अगस्त, 1972 को श्रीमती इन्दिरा गॉधी जी ने राज्यसभा में कहा था कि –''मेरा सदैव ऐसा विश्वास रहा है और मैं अब भी यह मानती हूँ कि भारत का बड़ा शत्रु पाकिस्तान नहीं है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु उसकी गरीबी और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है।''[2] लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में,भी पाकिस्तान की भारत–विरोधी नीति जारी है, इस प्रकार पाक की नीति और नीयत न कभी बदली है और न ही कभी बदलेगी।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान समय में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंधों का अध्ययन एवम् उनका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि विश्व के किसी एक राष्ट्र में घटित हुई घटनाओं का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर अवष्य ही पड़ता है, और कोई–भी राष्ट्र स्वयं अलग रहकर अपना सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। उसे दूसरे अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, आज प्रत्येक राष्ट्र परस्पर सहयोग के आधार पर पारस्परिक संबंधों को मजबूत एवम् प्रगाढ़ बनाने के लिये अग्रसर है। और यदि भारत–पाकिस्तान के मध्य संबंधों पर प्रकाश डाला जाये तो इस शोध–पत्र के माध्यम से मैंने भारत–पाकिस्तान संबंधों का अध्ययन इसलिये किया है क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत–पाकिस्तान ऐसे दो पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनके बीच देश–विभाजन से लेकर अब तक पारस्परिक संबंध कभी भी मधुर नहीं बन सके हैं, इन दोनों राष्ट्रों के मध्य वर्तमान समय में काश्मीर समस्या, चीन–पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीमा–पार आतंकवाद, ब्लूचिस्तान जैसे कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे विद्यमान है जिनका अध्ययन करना आधुनिक समय की मॉग है और इस विषय पर मेरे अध्ययन का उद्देश्य इन दोनों ही राष्ट्रों के बीच संबंधों एवम् समस्याओं को जानना तथा संबंधों को मधुर बनाने एवम् समस्याओं के निदान हेतु कुछ सुझाव प्रकट करना है। ताकि दोनों–ही राष्ट्रों के मध्य आपसी रिश्तों में तनाव को कम किया जा सके।

विश्लेषण

दक्षिण एशिया में भारत एवम् पाकिस्तान ऐसे दो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिनके बीच हमेशा–ही कटुता, वैमन्यस्य, संदेह, आपसी अविश्वास एवम् शत्रुता देखने को मिलती रही है और आपसी संबंध कभी–भी मधुर नहीं बन सके भारत ने तो अपने पड़ोसी के साथ हमेशा–ही संबंधों को मधुर बनाने का अथक प्रयास किया, चाहे वह क्रिकेट के माध्यम से हो अथवा आपसी विदेश सचिव वार्ता के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य तंत्र एवम् कट्टरपंथी संगठनों ने संबंधों को कभी–भी मधुर नहीं होने दिया। दरअसल पाकिस्तान का शासन, सेना एवम् कट्टरपंथी संगठनों के इशारों पर चलता है और पाकिस्तान सरकार भी इनके हाथों की कठपुतली मात्र है। भारत विश्व का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में आतंक, आईएसआई, सेना, सत्ता, समाज और राजनीति का एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जिसने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है और अब पाकिस्तान में लोकतंत्र को दरकिनार करते हुये सत्ता के शीर्ष पर सेना और कट्टरपंथी संगठन आ गये हैं।

भारत एवम् पाकिस्तान के बीच अब तक 1948, 1965, 1971, एवम् 1999 में चार युद्ध हो चुके हैं। पहली बार 22 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान सरकार की सहायता से कबाईलियों ने काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कबाईलियों ने काश्मीर के करीब 35,000 वर्गमील के स्थान पर कब्जा कर लिया जिसे उन्होंने 'आजाद काश्मीर' का नाम दिया। काश्मीर को हड़पने के लिये पाकिस्तान ने एक बार पुनः युद्ध का आश्रय लिया अभी भारत–पाक के बीच कच्छ रन समझौता ताजा ही था कि पाकिस्तान ने काश्मीर के छम्ब क्षेत्र पर सितम्बर, 1965 में विपुल टैंक शक्ति के साथ भीषण आक्रमण कर दिया भारत ने भी पाक के विरूद्ध सम्पूर्ण सीमा पर नये मोर्चे खोल दिये। और भारत के भीषण प्रहार से पाकिस्तान को नाको चने चबाने पड़े। इस युद्ध के बाद भारत–पाक के बीच 'ताशकंद समझौता' (10 जनवरी, 1966) भी हुआ इस समझौते के कारण भारत को वह सभी प्रदेश पाकिस्तान को वापस देने पड़े जो उसने अपार जन–धन की हानि उठाकर प्राप्त किये थे। ताशकंद समझौते के संबंध में कहा जाता है कि– ''ताशकंद समझौता दो देशों के बीच शांति का समझौता नहीं, बल्कि उनके (भारत और पाकिस्तान) मामलों में तीसरे देश (रूस) द्वारा हस्तक्षेप का समझौता है।''[3]

वर्ष 1971 में भारत–पाक के बीच पुनः युद्ध हुआ और बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ। हालाँकि इस बार भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी इस युद्ध के बाद भारत–पाक के बीच 'शिमला समझौता' (3 जुलाई, 1972) को हुआ। इस प्रकार शिमला समझौते में यह तय किया गया कि– ''दोनों पक्ष आपसी वार्ता द्वारा अपनी समस्याओं को हल करेंगे और एक–दूसरे के विरूद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे, एक–दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे और एक–दूसरे के प्रति घृणापूर्ण प्रचार नहीं करेंगे, पारस्परिक संपर्क सेवाओं की पुनः स्थापना करेंगें, दोनों सेनाऍ अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर लौट जायेंगी। और 17 दिसम्बर, 1971 के युद्ध–विराम की नियंत्रण रेखा को मान्यता देंगें। इस समझौतों के आलोचकों ने इसे 'जवानों के बलिदान की उपेक्षा', और 'जीती हुई भूमि' लौटाने के निश्चय पर तीव्र विरोध प्रकट किया।[4]

भारत–पाकिस्तान संबंधों को लेकर पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार जारी रहा। दोनों देशों के मध्य तनाव को कम करने और संबंधों को मधुर बनाने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 20 फरवरी, 1999 को दिल्ली–लाहौर उद्घाटन बस – यात्रा से जब लाहौर गये तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

नवाज शरीफ ने बाधा स्थित सीमा द्वार पर आकर 21 तोपों की सलामी के बीच उनका भव्य स्वागत किया तथा दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने लाहौर घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किये। अभी लाहौर घोषणा–पत्र की स्याही सूखने भी नहीं पायी थी कि भारत–पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग छिड़ गई जिस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी दिल्ली–लाहौर बस यात्रा द्वारा पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे उसी समय पाकिस्तान भारत के विरूद्ध शड़यंत्र करके उसके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भू–क्षेत्र कारगिल को हथियाने का स्वप्न देख रहा था। तब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल विजय अभियान छेड़ दिया। और 17 जुलाई, 1999 को भारतीय सैनिकों ने कारगिल की सबसे ऊँची चोटी 'टाईगर हिल्स' पर अपनी विजय का पताका लहराया और कारिगल संघर्ष में भारत की विजय हुई।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, भारत एवम् पाकिस्तान संबंधों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य उजागर होता है कि आजादी से लेकर अब तक हमारे पड़ोसी की 'कथनी और करनी' में कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमेशा ही पाकिस्तान का दोगलापन' भारत के सामने आया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि –''दुनिया के किसी–भी राष्ट्र को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है कि वह अपना पड़ोसी स्वयं चुन सके। क्योंकि जिस देश से हमारी भौगोलिक सीमाएँ लगती हैं, वह स्वयं पड़ोसी के दायरे में आ जाता है इसलिये दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं।'' इस प्रकार हमने हमेशा अपने पड़ोसी के समक्ष दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया लेकिन इसके बदले में हमारे सामने संसद पर आतंकी हमला और 26/11 जैसी दर्दनाक घटनाएं सामने आईं। पाकिस्तान ने प्रत्येक राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर द्विपक्षीय काश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। 13वें सार्क शिखर सम्मेलन (2005) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने सार्क नियमों के विरूद्ध जाकर काश्मीर का द्विपक्षीय मुद्दा उठाया।[5]

पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार ने भी संबंधों को मधुर बनाने की तमाम कोशिशें की और वर्ष, 2015 में भारत–पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ ऊफा वार्ता में पिघलती हुई दिखाई दी और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों नरेन्द्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच सद्भावनापूर्ण द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत की सहमति जताई। पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिये मोदी जी ने लाहौर की यात्रा की। लेकिन इसके बदले में उरी, गुरूदासपुरर, पठानकोट तथा पुंछ सेक्टर में आतंकी हमले ऐसी चोट है जो देश को लम्बे समय तक याद रहेगी। 29 सितंबर, 2016 की रात भारत ने उरी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से लिया और पुंछ में पाक सेना द्वारा की गई कार्यवाही का बदला लेने के मकसद से भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जबाव दिया भारतीय जवान सीमा–पार कर 500 मीटर तक अंदर चले गये थे इस पूरे अभियान को सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट–2 का नाम दिया।[6] आज चीन की शह पाकर पाकिस्तान भारत को ऑखें दिखा रहा है, पाकिस्तान की ओर से भारत को लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। दरअसल, भारत–पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करने में महाशक्तियों की भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है भले–ही आज अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य मदद देने पर रोक लगा दी है।

अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 25.5 करोड़ डॉलर यानी 1626 करोड़ रूपये से ज्यादा की सैन्य मदद पर रोक लगा दी है।[7] लेकिन एक वक्त था जब अमेरिका ने पूरी तरह पाकिस्तान को भारत के विरूद्ध सैन्य मदद पहुँचाई थी। वही आज पाकिस्तान और चीन के बीच घनिष्ठता जग जाहिर है उल्लेखनीय है, कि चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का एक बेहतरीन मोती ग्वादर है और इसलिए चीन पाकिस्तान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। महान् कूटनीतिज्ञ कौटिल्य ने कहा है कि–''शत्रु का शत्रु, सदैव अपना मित्र होता है।'' उनका यह कथन भारत चीन युद्ध के संदर्भ में सत्य प्रमाणित हुआ था।[8] 17 जुलाई, 1963 को विदेशमंत्री भुट्टो ने पाकिस्तान असेम्बली में यह घोषणा की कि–''यदि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वह देश अकेला नहीं होगा इसमें एशिया का सबसे बड़ा देश शामिल हो जायेगा।'' इस पर लंदन के टाइम्स ने यह टिप्पणी की थी कि– इससे प्रतीत होता है कि रावलपिण्डी और पीकिंग में सैनिक सहायता का गुप्त समझौता हो चुका है, इस बात की पुष्टि सितम्बर, 1965 में भारत–पाक युद्ध में चीन द्वारा भारत को दिये गये अल्टीमेटम से हो गई।[9] वर्ष 2015 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान की यात्रा पर गये थे तब उन्होंने कहा था कि–''पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से भी ऊँची, महासागर से भी गहरी और शहद से भी मीठी है।''[10]

इस प्रकार भारत–पाकिस्तान संबंधों को लेकर वर्तमान समय में, भारत प्रत्येक राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरने की तमाम कोशिशें कर रहा है, ताकि पाकिस्तान अलग–अलग पड़ जाये और वह मजबूर होकर अपनी भारत विरोधी नीति को बदल सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान स्वयं को बदल पायेगा ? क्या वहाँ की सेना सरकार को ऐसा करने की इजाजत देगी ?

पाकिस्तान को घेरने के लिये भारत के द्वारा भारत–पाक सिंधु जल समझौता तोड़ना, एमएफएन का दर्जा निरस्त करना, पाकिस्तानी एयरलाइंस को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देना, सार्क समिट का बहिश्कार करना, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पाक के मंसूबों को सभी के सामने उजागर कर देना षामिल है।[11] हाल ही में कुलभूशण जाधव के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान के विरूद्ध पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर ब्लूचिस्तान का मुद्दा भी उठाया है। जिनेवा में यूनाईटेड नेशन्स ह्यमन राइट्स काउंसिल के 33वें सेषन में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि– पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भारत की तरफ से कहा गया कि–पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जो कि बड़े सोचे–समझे तरीके से ब्लूचिस्तान और पीओके में लोगों के ह्यमन राईट्स को

कुचल रहा है।[12] इस प्रकार भारत का यह कथन उसकी सामरिक कूटनीति का एक अहम् हिस्सा है।

सुझाव

प्रथम, भारत–पाकिस्तान के मध्य काश्मीर मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करनी होगी। दूसरा, किसी विवादित स्थल (पीओके) पर कॉरिडोर बनाने के लिये सहमति देना और कॉरिडोर बनाना अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के विरूद्ध है, जिस पर भारत को आपत्ति दर्ज कर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सहारा लेना चाहिए। तीसरा, सुरक्षा–परिषद का पुनः नवीनीकरण किया जाना चाहिए ताकि भारत भी स्थायी सदस्य के रूप में षामिल हो सके। चौथा, भारत को सैन्य क्षेत्र में संसाधनों को जुटाने के साथ–साथ सैनिकों को नई तकनीकों से प्रषिक्षित करना होगा। साथ–ही सैनिकों को आधारभूत सुविधाएँ मुहैया करानी होगी। पाचवॉ, भारत के साथ–साथ समस्त विश्व को पाकिस्तान के विरूद्ध पीओके तथा ब्लूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। छटवॉ, भारत–पाकिस्तान के मध्य विवादों को समाप्त करने तथा संबंधों को मधुर बनाने के लिये आवश्यक है, कि विदेश नीति के दायरे में स्वार्थ पूर्ण घरेलू राजनीति को नहीं आने दिया जाये। सातवॉ, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे स्वार्थों की कमी नहीं है जो यह चाहते हैं कि भारत–पाकिस्तान के मध्य तनाव बना रहे। भारत को ऐसे देशों से सचेत रहना होगा।

निष्कर्ष

भारत–पाकिस्तान संबंधों पर इतना विचार मंथन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है, कि भारत जहॉ हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय शांति का पक्षधर रहा है वहीं पाकिस्तान की विदेश–नीति का मूलमंत्र सदैव युद्ध रहा है। भारत ने हमेशा–ही संबंधों को मधुर बनाने के लिये दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा–ही शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हुये दगाबाजी को अंजाम दिया। हालॉकि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे साथ छलावा किया उसका परिणाम हमारे पड़ोसी के लिये घातक रहा और पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। इतिहास में युद्धों से लेकर वर्तमान में सजिकल स्ट्राइक तक इसके उदाहरण मौजूद हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को ईंट का जबाव पत्थर से दिया है। अतः आवश्यकता इस बात की है, कि भारत को पाकिस्तान को प्रत्येक गंभीर मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर घेरना होगा। और ऐसी परिस्थितियॉ उत्पन्न करनी होगी कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग–थलग पड़ जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा, एम.एल., अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1970, पृष्ठ–518*
2. *वेदालंकार, हरिदत्त, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, सरस्वती सदन प्रकाशन, दिल्ली, 1978, पृष्ठ–444*
3. *कौशिक, पीताम्बरदत्त, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, रामप्रसाद एण्ड संस प्रकाशन, आगर, 1966, पृष्ठ–519*
4. *पाल, शिवम, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, वंदना पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ–266*
5. *भारद्वाज, रामदेव, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और समसामयिक राजनीतिक मुद्दे, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2010, पृष्ठ–221*
6. *राज एक्सप्रेस, 27 दिसंबर, 2017, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ–6*
7. *राज एक्सप्रेस, 3 जनवरी, 2018, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ–6*
8. *श्रीवास्तव, नरेन्द्रनाथ, आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, कैलाश पुस्तक सदन पब्लिकेशन, ग्वालियर, 1976, पृष्ठ–281*
9. *वेदालंकार, हरिदत्त, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, सरस्वती सदन प्रकाशन, दिल्ली, 1971, पृष्ठ–585*
10. *हरिभूमि, 25 अप्रैल, 2015, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ–4*
11. *राज एक्सप्रेस, 27 सितम्बर, 2017, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ–6*
12. *राज एक्सप्रेस, 19 सितम्बर, 2016, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ–6*